अध्याय II : कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान

2.1 कपटपूर्ण छुट्टी यात्रा रियायत दावों की प्रतिपूर्ति

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के कर्मचारियों ने नकली छुट्टी यात्रा रियायत दावे प्रस्तुत किए जिनके परिणामस्वरूप ₹7.06 लाख की अनियमित प्रतिपूर्ति हुई।

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (मंत्रालय) द्वारा जारी दिनांक 26 सितम्बर 2014 के कार्यालय ज्ञापन में प्रावधान है "सभी पात्र सरकारी कर्मचारी अपने होम टाउन एलटीसी के एक ब्लॉक को बदल कर उसके बदले पूर्वोत्तर क्षेत्र/अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह/जम्मू एवं कश्मीर में किसी स्थान की यात्रा के लिए छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) का लाभ उठा सकते हैं। हवाई यात्रा के पात्र कर्मचारी यह एलटीसी अपने मुख्यालय से इकॉनॉमी क्लास में ले सकते हैं। हवाई यात्रा इकॉनॉमी क्लास में तथा एलटीसी-80 किराए अथवा कम पर केवल एयर इण्डिया द्वारा ही की जा सकती है। हवाई टिकटें सीधे एयरलाइन्स (एयर इण्डिया के बुकिंग कांउटरों, वेबसाइट) से अथवा प्राधिकृत यात्रा एजेंटों अर्थात मै. बॉमर लॉरी एण्ड कम्पनी, मै. अशोक ट्रेवल्स एण्ड टूअर्स तथा भारतीय रेलवे खानपान तथा पर्यटन निगम" की सेवाओं का प्रयोग करके ही खरीदी जानी चाहिए।

वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) के कर्मचारियों के एलटीसी अभिलेखों की नमूना जांच से उसके चार कर्मचारियों[1] द्वारा दावों की धोखाधड़ी का पता चला जिन्होंने हवाई यात्रा एयर इण्डिया द्वारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए की थी। लेखापरीक्षा ने कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत दावों का एयरलाईन द्वारा उपलब्ध कराए गए ब्यौरों से मिलान किया और पाया कि दावों के साथ प्रस्तुत किए गए बिल जाली थे। कर्मचारियों द्वारा दावा किए गए किराए एयरलाईन को वास्तव

[1] 2 मुख्य तकनीकी अधिकारी, 1 तकनीकी अधिकारी तथा 1 वरिष्ठ वैज्ञानिक।

में दी गई राशि से अधिक थे। इसके अतिरिक्त इन मामलों में हवाई टिकटें वर्तमान नियमों/अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए निजी एजेंटों के माध्यम से बुक कराई गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹7.06 लाख की राशि के दावों की अनियमित प्रतिपूर्ति की गई।

इसे बताए जाने पर (जून 2016), आईएआरआई ने बताया (सितम्बर 2016) कि कर्मचारियों को किए गए एकमुश्त भुगतान की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

मामला जुलाई 2016 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।